



स्वच्छ भारत मशिन ग्रामीण की प्रगति की समीक्षा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने **स्वच्छ भारत मशिन ग्रामीण (SBM-G)** को दृढ़ करने के लिये पंजाब, मध्य प्रदेश और बिहार के ग्रामीण स्वच्छता के लिये ज़िम्मेदार राज्य मंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की।

- इस सत्र का उद्देश्य प्रगति का आकलन करना, चुनौतियों से निपटना तथा ग्रामीण भारत में स्थायी स्वच्छता परियोजना सुनिश्चित करने के लिये रणनीतियों को कारगर बनाना था।

मुख्य बढि

- केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छता को एक व्यवहारिक मशिन बताया जो ग्रामीण समुदायों के स्वास्थ्य और सम्मान के लिये महत्वपूर्ण है।
- उन्होंने सामूहिक प्रयासों के माध्यम से स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत के निर्माण के महत्त्व को रेखांकित किया तथा कहा कि प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की अपनी अलग-अलग चुनौतियाँ हैं, लेकिन स्वच्छ भारत प्राप्त करने का लक्ष्य उनका समान है।
- राज्यवार प्रगति:
 - मध्य प्रदेश:
 - 99% गाँव खुले में शौच मुक्त (ODF) प्लस स्थिति वाले हैं, जिनमें से 95% ने ODF प्लस मॉडल का दर्जा प्राप्त कर लिया है।
 - राज्य ने RRDA भोपाल के साथ समझौता ज्ञापन सहित नवीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पहल को क्रियान्वित किया।
 - उत्तर प्रदेश:
 - 98% गाँव ODF प्लस हैं। SBM-G उद्देश्यों के लिये 1 लाख से अधिक कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है।
 - प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिये अपशिष्ट से ऊर्जा मॉडल और स्कैप डीलर संपर्क पर ध्यान केंद्रित किया गया।
 - बिहार:
 - 92% गाँव ODF प्लस हैं। ग्रे वाटर मैनेजमेंट कवरेज 91% है और टोस अपशिष्ट प्रबंधन 80% है।
 - प्रयास कम प्रदर्शन करने वाले जिलों में परियोजनाओं को बेहतर बनाने पर केंद्रित हैं।
 - पंजाब:
 - 98% गाँव ODF प्लस हैं, जिनमें से 87% ने ग्रे वाटर प्रबंधन संतृप्ति प्राप्त कर ली है।
 - उन्नत प्रणालियाँ विकसित की जा रही हैं।
- सामूहिक कार्रवाई के लिये मंत्री का मार्गदर्शन:
 - ODF प्लस स्थिति: ODF प्लस मॉडल गाँवों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिये मज़बूत नगिरानी तंत्र स्थापित करना।
 - अपशिष्ट प्रबंधन अंतराल : घरेलू स्तर के समाधानों को प्राथमिकता देकर टोस और धूसर जल प्रबंधन में अंतराल को दूर करना।
 - सामुदायिक स्वच्छता: सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की कार्यक्षमता और परसिंपत्ता प्रबंधन को मज़बूत करना।
 - प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: पुनर्चक्रणकर्त्ताओं के साथ साझेदारी बनाना और वसितारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) ढाँचे का उपयोग करना।
 - EPR उत्पादकों को उनके उत्पादों के जीवन चक्र के दौरान उनके पर्यावरणीय प्रभावों के लिये ज़िम्मेदार बनाता है। इसका उद्देश्य बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना और नगर पालिकाओं पर बोझ कम करना है।
 - व्यवहार में परिवर्तन: लक्षित IEC (सूचना शिक्षा और संचार) अभियानों के माध्यम से शौचालय के नरितर उपयोग और अपशिष्ट पृथक्करण को बढ़ावा देना।
 - समुदाय-नेतृत्व वाले दृष्टिकोण: राज्यों को समुदाय-नेतृत्व वाले स्वच्छता प्रयासों को बढ़ावा देने के लिये महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों, स्थानीय नेताओं और नज़ी क्षेत्र के उद्यमों को शामिल करना होगा।
- व्यापक दृष्टिकोण और वैश्विक संरेखण:
 - स्वच्छ भारत मशिन ग्रामीण परिवर्तन की आधारशिला है, जो स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण और सामुदायिक कल्याण को एकीकृत करता है।
 - यह मशिन वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप है, जसिमें SDG 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता) और SDG 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) शामिल हैं।
 - इसका ध्यान लक्ष्य से आगे बढ़कर स्वास्थ्य, सम्मान और आत्मनिर्भरता के पारसिथितिकी तंत्र के निर्माण पर केंद्रित है।

स्वच्छ भारत मशिन ग्रामीण (SBM-G)

परिचय:

- इसे वर्ष 2014 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिये लॉन्च किया गया था।
- इस मशिन को एक राष्ट्रव्यापी अभियान/जनआंदोलन के रूप में क्रियान्वित किया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करना था।

स्वच्छ भारत मशिन (G) चरण-I:

- 2 अक्टूबर, 2014 को SBM (G) के शुभारंभ के समय देश में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 38.7% बताया गया था।
- मशिन के शुभारंभ के बाद से 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप, सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों ने 2 अक्टूबर, 2019 तक खुद को ODF घोषित कर दिया है।

SBM (G) चरण-II:

- यह चरण-I के अंतर्गत उपलब्धियों की स्थिरता पर जोर देता है तथा ग्रामीण भारत में ठोस/तरल एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) के लिये पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करता है।
- इसे वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक मशिन मोड में कार्यान्वित किया जाएगा, जिसका कुल परव्यय 1,40,881 करोड़ रुपए होगा।
- ODF प्लस के SLWM घटक की नगिरानी 4 प्रमुख क्षेत्रों के आउटपुट-आउटकम संकेतकों के आधार पर की जाएगी:
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन
- जैवमिनीकरणीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (पशु अपशिष्ट प्रबंधन सहित)
- ग्रेवाटर (घरेलू अपशिष्ट जल) प्रबंधन
- मल-कीचड़ प्रबंधन।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/review-of-swachh-bharat-mission-gramin-progress>

